ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेज: 4
महामारी में भी जारी है अमेजन जंगलों की कटाई

रविवारीय, 19 - 25 अप्रैल 2020 वर्ष- एक, अंक-37, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्य: 2 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

लॉकडाउन से पर्यावरण को संजीवनी

मुख्य संवाददाता

रांची : कोरोना महामारी से जहां विश्व एक ओर तबाह है, वहीं इसका एक दुसरा सुखद पक्ष भी पर्यावरण के मोर्चे पर सामने आया है। सारे विश्व में किसी भी प्रकार के प्रदूषण में कमी आयी है। वायु, जल, थल पर तो प्रदूषण में व्यापक कमी आयी ही हैं इसके अलावा मानसिक शांति के लिये खतरा बने ध्वनि प्रदूषण में भी बहुत ज्यादा गिरावट आयी है। सड़कों पर वाहन न के बराबर हैं, रेल सेवायें बंद है, हवाई जहाज एयरपोर्ट्स पर खड़े हैं। सड़कों से ट्रैफिक और बाजार के बंद होने से शोर नहीं है। और सर्वत्र शांति दिख रही है।

देश भर की नदियों और जलाशयों में गंदगी की मात्रा कम हुई है , दिल्ली में नर्क का पर्याय बने यमुना नदी के प्रदूषण में भी कमी आयी है। गंगा के किनारे बसे शहरों में ये देखा गया है कि घाटों पर जल ज्यादा स्वच्छ और पारदर्शी हैं जिसमें मछलियां किनारों पर आकर लोगों के फेंके गये चारे और अनाज को खा रही हैं। शहरों में सन्नाटा देख जंगली जानवर भी घुस जा रहे हैं, सुबह में चीड़ियों की चहचहाहट बढ़ गयी है। एक शहर से दूसरे शहरों के पहाड़ों के शिखर वायु प्रदूषण और धुंध के खत्म होने से स्पष्ट दिखने लगे हैं। कोरोना ने मानवों में भय का संचार तो किया है पर उन्हें संयम से रहने की सीख देने के अलावा प्रकृति से खिलवाड़ न करने की चेतावनी भी दे रहा है।

तस्वीर रांची के सबसे घने रिहायशी इलाके रातू रोड की ओर से कांके डैम के जुड़े वेट लैंड की है जहां शोर गुल कम होने से बगुलों की तादाद बढ़ गयी है

फिर से दिखने लगी रामगढ़ की पहाड़ियां

सालों पहले रांची पहाड़ी से रामगढ और हजारीबाग की ओर चुटुपालु घाटी की पहाड़ियां स्पष्ट नजर आती थीं। ये दृश्य बहुत मनोरम होता था। धीरे - धीरे प्रदूषण और धुंध के कारण ये सब दिखना बंद हो गया। कभी कभार बारिश होने के बाद धूल गर्द के कम होने पर ही रांची से चुटुपालु की ये पहाड़ियां नजर आती हैं। लेकिन लॉकडाउन में प्रदूषण के कम होने और धुंध धूलकणों के घटने से ये पहाड़िया फिर से नजर आने लगीं हैं। हालांकि ये दृश्य मौसम पर भी निर्भर करता है। बादलों के छा जाने पर ये दृश्य गायब हो जाता है। कुछ ऐसा ही वाकया पंजाब के बारे में भी बताया जा रहा है कि, वहां के कुछ शहरों से हिमाचल के बर्फीले पहाड़ दिखने लगे हैं जो दशकों पहले कभी दिखा करते थे।

अब परिंदों के शोर से नींद खुल रही है

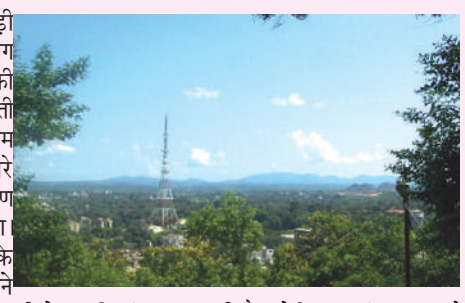

दिल्ली से पड़ोसी शहर नोएडा में पूरा मंज़र बदला नज़र आता है।आज कल लोगों की सुबह अक्सर नींद अलार्म से नहीं, परिंदों के शोर से खुलती है। जिनकी आवाज़ भी हम भूल चुके थे। बालकनी में जाएं, तो नज़र ऐसे आसमान पर पड़ती है, जो अजनबी नज़र आता है। इतना नीला आसमान, दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले बहुत से लोगों ने ज़िंदगी में शायद पहली बार देखा हो। फ़लक पर उड़ते हुए सफ़ेद रूई जैसे बादल बेहद दिलकश लग रहे थे। सड़कें वीरान तो हैं, मगर मंज़र साफ़ हो गया है। सड़क किनारे लगे पौधे एकदम साफ़ और फूलों से गुलज़ार। यमुना नदी तो इतनी साफ़ कि पूछिए ही मत। सरकार हज़ारों करोड़ ख़र्च करके भी जो काम नहीं कर पाई लॉकडाउन के 21 दिनों ने वो कर दिखाया।

ऐसी ही तस्वीरें दुनिया के तमाम दूसरे शहरों में भी देखने को मिल रही हैं। इसमें शक नहीं कि नया कोरोना वायरस दुनिया के लिए काल बनकर आया है। इस वायरस ने हज़ारों लोगों को अपना निवाला बना लिया है। इन चुनौतियों के बीच एक बात सौ फ़ीसद सच है कि दुनिया का ये लॉकडाउन प्रकृति के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। वातावरण धुल कर साफ़ हो चुका है। हालांकि ये तमाम क़वायद कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि कार्बन उत्सर्जन रुक गया है। अमरीका के न्यूयॉर्क शहर की ही बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल वहां प्रदूषण 50 प्रतिशत कम हो गया है।

मूल सवाल कि क्या हम इसे बरकरार रख पायेंगे?

लॉकडाउन ने पर्यावरण का उस स्तर में परिष्कार किया है जिसकी कल्पना हम नहीं कर पा रहे थे। दिल्ली मुंबई सहित देश के छोटे शहरों कस्बों तक में पर्यावरण प्रदूषित था और सरकार, विभाग, एनजीओ से लेकर पर्यावरणविद् तक इसकी चिंता कर रहे थे और अपने स्तर से प्रदूषण स्तर को घटाने का प्रयास भी कर रहे थे। लेकिन वह सब प्रयास तकरीबन बेकार ही साबित हो रहा था, लेकिन लॉकडाउन ने जहां रेल, मोटर वानि, वायु परिवहन से लेकर छोटे मोटे मशीनों तक को ठप्प कर दिया इस कारण से शोर भी बंद हो चुका है। शहरों में भी गावों की तरह सन्नाटा है। सुबह में पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा है। नदियां साफ हुई हैं। ये सभी बदलाव सुखद तो हैं, पर इस सुखद बदलाव से सीख लेकर क्या देशवासी प्रदूषण और पर्यावरण के प्रति ज्यादा गंभीर होंगे? एक भय यह भी है कि लॉकडाउन के बाद ज्यादतर लोग अपने रोजमर्रा के काम में टूट पड़ेंगे वो बंदी के दरम्यान अपने नुकसान की भरपाई के लिये दिन रात काम करेंगे तब इस आपाधापी में पर्यावरण और प्रदूषण का मुद्दा गौण हो जायेगा?

कुछ लोगों का कहना है कि लंबे समय ये उन्होंने मांसाहार नहीं किया, कुछ लांग ड्राइव पर नहीं गये है, जहां तहां लोग फंसे हुये हैं। लॉकडाउन की समाप्ति पर सबसे ज्यादा परिवहन पर बोझ होगा और तब शोर, ट्रैफिक, वायु प्रदूषण पहले की तरह ही बढते चला जायेगा।

कोरोना योद्धाओं को दिल से सलाम : मुख्यमंत्री

रांची :मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य में कोरोना से पीड़ित चार मरीज बिल्कुल स्वस्थ घोषित होने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि इस महामारी से हमारी जंग में जीत का यह आगाज है। राज्यवासियों के सहयोग से हम महामारी पर जल्द ही विजय प्राप्त करेंगे। कोरोना से इस लड़ाई में कोरोना योद्धाओं को दिल से सलाम। इस लड़ाई में स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी, सखी मंडल की बहनों, संगठनों, आदि जैसे कई योद्धाओं का दिल से आभार प्रकट करता हूं। आप सभी दिन-रात एक कर कोरोना को हराने की मुहिम में अनवरत लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारियों एवं चिकित्सकों को बधाई। आपके लगन, मेहनत एवं अदम्य साहस के बल पर हमें इस महामारी से निजात अवश्य मिलेगी।

लॉकडाउन में किसानों को बीएयू वैज्ञानिकों का परामर्श

संवाददाता

रांची :भारत सरकार द्वारा लॉक डाउन -2 में कृषि क्षेत्र की गतिविधियों में छुट से किसानों को रबी फसल गेहुँ, चना, मसूर, मटर, सरसों एवं तीसी की कटाई, कटाई उपरांत सफाई, सखाई, छंटाई, ग्रेडिंग, भंडारण, पैकेजिंग एवं विपणन का मार्ग सुगम हो गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने इस छुट का लाभ लेने के लिए किसान हित में परामर्श दिया है।

डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन डॉ आरएस कुरील ने बताया कि प्रदेश के जिलों में स्थित कृषि विज्ञान विज्ञान केन्द्रों (केवीके) के वैज्ञानिकों को लॉक डाउन -2 में भारत सरकार के दिशा - निर्देशों के पालन हेतु स्थानीय किसानों को जागरूक करने को कहा है।

डीन एग्रीकल्चर डॉ एमएस यादव ने राज्य के किसानों को कृषि कार्यो में भी सामाजिक दूरी के तहत कम से कम मजदूर का उपयोग एवं तीन-चार

फीट की दूरी बनाए रखने, साबुन से अच्छी तरह हाथ धोकर कृषि कार्य शुरू करने, प्रत्येक दो-तीन घंटे के अंतराल में साबुन से हाथ धोने और हर दिन नया साफ कपडा पहनने की सलाह दी है।

एसोसिएट डीन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग प्रो डीके रूसिया ने फसल कटाई में मशीन चालित यंत्रो का उपयोग करने, खुद को सेनेटाईज करने, हस्त चालित कृषि उपकरणों को दिन में तीन-चार बार साबुन के पानी से धोने तथा प्रत्येक व्यक्ति को अलग - अलग कृषि उपकरण उपयोग करने को कहा है।

कृषि मौसम एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ अब्दुल वदूद ने बताया कि मौसम में उतार - चढ़ाव के कारण रबी फसल को पकने में थोड़ी देरी हुई है। लॉक डाउन ने भी फसल कटनी को प्रभावित किया है। अगले कुछ दिनों तक बारिश और अतिवृष्टि का मौसम पूर्वानुमान देखते हुए उन्होंने किसानों को रबी फसलों की अविलंब कटाई करने, कटे फसल का छोटे - छोटे बंडल बनाकर सुरक्षित स्थान में रखने को कहा है।

विभिन्न फसलों के कृषि वैज्ञानिकों में डॉ सूर्य प्रकाश, पौधा प्रजनक (गेहुँ) ने बढ़ते तापक्रम से गेहुँ फसल पककर तैयार होने और मौसम पूर्वानुमान के आधार पर जल्द - से - जल्द कटाई पूरी कर दौनी (थ्रेशिंग) करने और अच्छी तरह सुखाकर गेहुँ के दाने का भंडारण करने की सलाह दी है। दाने का कीड़ो से बचाव के लिए सेल्फोस पाउच या टिकिया या नीम की सुखी पत्ती का उपयोग करने को कहा है।

डॉ कमलेश्वर प्रसाद, पौधा प्रजनक (चना) ने खेतों में चना फसल पूर्णतया परिपक्व होने की बात कही। उन्होंने चना फसल की तुरंत

अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री वितरण के लिए चलाई गई विशेष मेडिकल ट्रेन

रांची :कोरोनावायरस से बचाव के लिये भारतीय रेल भी सभी स्तर पर अथक प्रयास कर रहा है। इसी के तहत दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय से एक विशेष मेडिकल ट्रेन संतरागाछी – हटिया – संतरागाछी के बीच चलाई गई ।इस विशेष पार्सल ट्रेन में अत्यंत महत्वपूर्ण मेडिकल के उपकरण, पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर तथा दवाइयां का वितरण दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर, चक्रधरपुर, रांची एवं आद्रा चारों मंडलों में किया गया। यह ट्रेन खड़गपुर – टाटा चक्रधरपुर – हटिया – आद्रा से होते हुए चलाई गई थी।इस विशेष मेडिकल ट्रेन में सभी रेलकर्मी थे। इस ट्रेन में सभी रेल कर्मचारियों का स्टेशन पर ही कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव के लिए सारे प्रोटोकॉल का पालन किया गया था। इस विशेष मेडिकल पार्सल ट्रेन के चलने से दक्षिण पूर्व रेलवे के चारों मंडलों के अस्पतालों में मेडिकल उपकरण एवं दवाइयों के पहुंचने से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम करने में महत्वपूर्ण सहायता मिली है।

महामारी से सबक

गांवो कस्बों को सक्षम बनाना ही होगा

मनोज कुमार शर्मा

महामारी के इस समय में सबसे ज्यादा खबरें महानगरों में फंसे मजदूरों की आ रही हैं। लॉकडाउन की स्थिति में ये अपने गावों कस्बों की ओर पैदल ही चल पड़े थे। बहुत सारे रास्तों में हीं पकड़ कर क्वारेंटाइन कर दिये गये जहां ज्यादतर की हालत खराब है, कुछ भूख प्यास , दुर्घटना से मारे गये, इनमें से कुछ जब अपने गांवों में पैदल ही पहुंचे तो अपने ही लोगों ने इन्हें घर में घुसने नही दिया, कुछ को गांव के बाहर ही रहने को कहा गया और कुछ के बारे में पुलिस को सूचना दे दी गयी और पुलिस ने इन्हें क्वारेंटाइन में भेज दिया।

पांच करोड़ मजदूर तो सिर्फ बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के हैं जो गिने चुने महानगरों में जाकर काम करते हैं। और उस महानगर की जो क्षमता है उससे ज्यादा आबादी इन्हीं के कारण है। राजनीतिक और कानूनी कारणों से इन्हें भगाने या हटाने की बात कोई नहीं कहता लेकिन ये हकीकत है कि अगर हमारे गांव सक्षम रहते तो इनमें से एक बड़ी आबादी कभी इन महानगरों का रूख नहीं करती। बिहार की ग्रामीण अर्थव्यस्था इन बाहर गये मजदूरों की बदौलत चलती है। ऐसा भी नहीं कि ये मजदूर दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। कुछ

गावों कस्बों में रोजगार सृजन न होने के कारण करोड़ो लोग गिनती के कुछ महानगरों में जा घुसे हैं महानगरों में क्षमता से ज्यादा आबादी है वहीं गांव वीरान हो रहे हैं। कोरोना ने ये मौका दिया है कि हम गावों को नये सिरे से सृजित करें।

सालों पहले पटना में छठ के समय गंगा में एक स्टीमर डूब गयी थी और कई दर्जन लोग काल के गाल में समा गये थे। कारण था कि अच्छे घाट को लूटने के लिये स्टीमर के एक ही सिरे पर सारे लोग जमा हो गये थे और असमान बोझ से नौका पलट गयी। कुछ ऐसा ही बोझ हमारे महानगरों पर है।

ही महिने पहले दिल्ली में एक फैक्ट्री में आग लगी और उसमें दर्जनो बिहारी मजदूर जल कर मर गये, बाद में पता चला कि उस फैक्ट्री के ही संकरी जगहों पर ये मजदूर रहते भी थे। एक ही कमरे में कई कई लोगों का रहना और कमाई बचा कर साल में एक दो बार गांव आना जरूरी कामों में खर्च कर वापस महानगरों में लौट जाना। ये गांव के लिये फौरी राहत हो सकता है स्थाई इंतजाम नहीं। हम पढते आये हैं कि गंगा का मैदान काफी उपजाऊ है, लेकिन इसी उपजाऊ मैदान में खेती के लिये पैसे कमाने लोग महानगरों में है और गांव नये बदलाव से वंचित है। यूरोप अमेरिका में भी गांव हैं वहां किसानों को सम्मान से अन्नदाता की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे यहां खेती ज्यादतर के लिये मजबूरी है और गांव में वही है जो बेरोजगार है।

इस स्थिति को ग्रामीण खुद नहीं बदल सकते, ये काम सरकारों को करना होगा? हम सिर्फ सबिसिडी, ऋण, रियायत से गांवों से पलायन नही रोक सकते। सबसे आवश्यक है कि गांवों में वो साधन, आमदनी सृजित करें जिसके लिये लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। गांवो में वैसे उद्योग बहुतायत में खड़े करने होंगे जो वहीं के उत्पाद और कच्चे पदार्थों को खरीद कर प्रोसेस कर सकें, ग्रामीणों को नकदी तुरंत मिले और उनके उत्पादों की वाजिब कीमत भी मिले तभी महानगरों का मोह कम होगा? अभी लॉकडाउन में ये खबरें भी आ रही हैं कि ग्रामीणों ने दूध सड़क पर बहा दिया और सब्जियों को अपने मवेशियों को खिला दिया। सरकारें इस मामले में उदासीन और लापरवाह रही हैं। झारखंड में रूक्का में पिछली सरकार ने एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनवाया और करोड़ो की लागत के बाद भी उसे चालू नहीं करवा सकी। बाद में उसे लीज पर देने की बात भी सुनाई दी।

एक और बड़ी समस्या बिहार जैसे राज्यों में खास तौर से है कि सक्षम होने के बाद भी लोग महानगरों में चाकरी करने जाते हैं, क्योंकि गावों में समुचित जीवनयापन के बाद भी उन्हें सम्मान नहीं मिलता उन्हें बाहर जाने पर ही सम्मानित माना जाता है।

स्पष्ट है सरकारों ने ग्रामीण विकास पर शोर तो खूब किया, पर वैसा काम बहुत कम किया गया जो इन राज्यों से मजदूरों के पलायन को रोक सके। यानि कोरोना संकट खत्म होते ही ये पलायन फिर से महानगरों की ओर होगा।

ग्रामीण विकास का झूठ

लॉकडाउन की बहुत बड़ी मार ग्रामीणों और किसानों पर पड़ी है। रांची के आस पास के ग्रामीण इलाकों में पशुपालकों ने दूध सड़कों पर बहा दिये। क्यों कि बंदी में दूध के खरीददार नहीं मिले तो कहीं ट्रांसपोर्ट की समस्या आ गयी। उन्होंने दस रूपये लाटर भी दूध बेचा ताकि मवेशियों के लिये चारे का इंतजाम किया जा सके। वहीं शहरों में दूध बेचने वालों ने दूध की कीमत में इजाफा कर दिया। उनका कहना था कि लॉकडाउन में पशुचारे की कमी है और हमें महंगा खरीदना पड़ रहा है।

कुछ किसानों ने सब्जी खेत में ही मवेशियों के खाने के लिये छोड़ दिया। रही सही कसर हाल में प्राकृतिक आपदा ने पूरी कर दी। बेमौसम ओलावृष्टि ने कर्ज लेकर खेती किये गये सब्जियों और स्ट्राबेरी जैसी फसलों को बर्बाद कर दिया।

ये सारे वाकये बता रहे हैं कि सरकारों ने राज्य में ग्रामीण विकास का जितना शोर किया उतना धरातल पर नहीं उतरा। झारखंड के गांवों में आज भी सब्जी उपजाने वाला किसान उस आमदनी को नहीं प्राप्त कर पाता है जिसका वो हकदार है। इस काम में वो माफिया हावी हैं जो एक मिर्ची तक नहीं उपजाते। कई बार ऐसी खबरें भी सुनने को मिलती हैं कि किसानों ने अपने उपज मंडी में ही छोड़ दिये क्योंकि उन्हें वापस ढो कर घर ले जाने में जो खर्च था वो भी दंड था। कोल्ड स्टोरेज की कमी और वहां छोटे किसानों के लिये बंद दरवाजे की खबरें हम अक्सर सुनते रहे हैं। लेकिन सरकारों ने भी कभी इसके निदान के लिये ठोस पहल नहीं किये हैं।

> पिछली झारखंड सरकार ने रुक्का में ताम झाम से फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनवाया, लेकिन वह चालू नहीं हो सका। क्यों चालू नहीं हुआ ये आज तक रहस्य है, अखबारों में छपा कि शीतलक नहीं होने के कारण ये चालू नहीं हुआ। ये हास्यास्पद बात है कि जिस सरकार ने करोड़ो खर्च कर प्लांट बनवाया वो ही तो शीतलक भी लगवा सकती थी? पर नहीं ऐसा नहीं हुआ और प्लांट बेकार हो गया, उसे लीज पर देने की बात भी हुई थी। अगर ये प्लांट समय पर चालू हो जाता तो क्षेत्र के ग्रामीणों के उत्पाद आज सड़क पर नहीं फेंके जाते और न ही चारे के रूप में मवेशियों को खिलाये जाते। यानि विकास का सिर्फ झूठा शोर हुआ

कुछ साल पहले किसी कंपनी ने लोहरदगा के कुडू में एक महिला को एलोवेरा की खेती करवा दी और उसकी उपज को खरीदने का करार भी कर लिया, लेकिन उपज तैयार होने पर वह कंपनी भाग निकली । झारखंड में किसान बहुत परिश्रमी और प्रयोगधर्मी भी हैं पर उनके उत्पाद और उपज की अगर सही कीमत नहीं मिली और समय पर खरीददार भी नहीं मिले तो कृषि से उनका मोह भंग होगा ही । और महानगरों की ओर पलायन रोकने की बात सिर्फ सरकारी लफ्फाजी ही बनी रहेगी।

दस्ताने से बढ़ सकता है कोरोना का खतरा

कोरोना वायरस के डर से लोगों ने दस्ताने खरीद तो लिए हैं लेकिन ये डिस्पोजेबल ग्लव्स क्या वाकई आपको वायरस से बचा सकते हैं? बीमारी से बचने के लिए दस्तानों का इस्तेमाल जाहिर सी बात है।

ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ग्लव्स पहनते हैं। बीमार लोगों की देखभाल के दौरान नर्स भी ग्लव्स पहनती हैं। मकसद यह होता है कि इलाज करने वाला मरीज के खून या शरीर से निकलने वाले किसी भी तरल के संपर्क में ना आए। बैक्टीरिया या वायरस से ये बहुत ही कम वक्त के लिए ही बचा पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लव्स जिस मैटीरियल से बने होते हैं वह पोरस होता है। जितनी ज्यादा देर तक इन्हें पहन कर रखा जाएगा कीटाणुओं के दस्ताने के भीतर घुस कर त्वचा में पहुंचना उतना आसान होता रहेगा। यही वजह है कि अस्पताल में काम करने वाले लोग बार बार दस्ताने बदलते हैं और हर बार उन्हें उतारने के बाद डिसइन्फेक्टेंट से अपने हाथ अच्छी तरह साफ करते हैं। यानी ग्लव्स पहनने का मतलब यह नहीं होता कि हाथ धोने से छुट्टी मिल गई ग्लव्स के झांसे में ना आएं । डिस्पोजेबल ग्लव्स विनायल, लेटेक्स या फिर नाइट्राइल के बने होते हैं। इन्हें पहन कर सुरक्षा का अहसास तो होता है। लेकिन यह अहसास आपको धोखा दे सकता है। जब लोग सामान खरीदने के लिए ग्लव्स पहन कर घर से बाहर निकलते हैं तो कोशिश जरूर करते हैं कि चेहरे को हाथ ना लगाएं लेकिन चूक तो हो ही सकती है। और खरीदारी के दौरान अगर आप ग्लव्स पहन कर अपने फोन को छू रहे हैं तो वायरस आसानी से आपके फोन की सतह पर फैल सकता है। फिर घर जा कर आप भले ही दस्ताने उतार कर फेंक दें लेकिन फोन को तो दोबारा हाथ में लेंगे ही। और वायरस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शरीर के अंदर नंगे हाथों से जाना है या ग्लव्स के जरिए।

पान की खेती करने वालों को लॉकडाउन से नुकसान

बुंदेलखंड में पान की खेती करने वाले किसानों की कमर लॉक-डाउन ने तोड़ दी है। शहरों को सप्लाई करने के लिए तोड़े गए पान घरों में रखे-रखे बेकार हो गए जिन्हें मजबूर किसानों ने कू-ड़े में फेंक दिया। खराब पान की कीमत डेढ़ करोड़ से भी ऊपर बताई जा रही है। वहीं बाजार बंद होने के कारण किसानों ने बरेजों में लगे पान नहीं तोड़े तो यह भी पककर बेल से गिरने लगे हैं। अब किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पान को लेकर जाएं भी तो कहां। मंडियां बंद पड़ी हैं। पान की दुकानों पर ताले हैं। शौकीन घरों में कैद हैं। पान की खेती करने वाले किसान इस समय बड़ा नुकसान झेल रहे हैं। जब लॉक-डाउन हुआ था तब सभी किसानों ने पान तोड़कर रख रखा था। लेकिन अचानक सब कुछ बंद हो गया। पान अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रखा जाता लिहाजा मजबूरी में पान फेंकना पड़ा।

क्या लॉकडाउन जानवरों के लिए वरदान है?

मुरली

कोरोना वायरस के कहर के बीच जहां दुनियाभर की सभी सार्वजनिक जगहों पर ताला लगा हुआ है, वहीं सभी जू और नेशनल पार्क भी बंद हैं। नेशनल पार्कों और चिड़ियाघरों में रह रहे जानवरों को तालाबंदी के बीच भी देखरेख की जरूरत पड़ती है।

लॉकडाउन से जिंदगी शांत भले ही दिख रही हो, घरों की चारदीवारियों और इंसानों के अंदर बहुत ही उथल पुथल हो रही है। जानवरों की जिंदगी भी सामान्य नहीं रही। कोरोना वायरस का खतरा भी अब जानवरों तक पहुंच गया है। भारत में तालाबंदी से खाने पीने और कई जरूरी सामानों की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। ये मुसीबत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि इंसानों पर निर्भर जानवरों के लिए भी है। मार्च के महीने से ही भारत के कई राज्यों में लगी अलग अलग पाबंदियों के चलते देश के सभी बड़े-छोटे चिड़ियाघर बंद हैं। फिर 5 अप्रैल से लागू देशव्यापी लॉकडाउन के चलते सभी कसाईघरों को भी बंद कर दिया गया है। चिड़ियाघरों के अंदर बंद जानवर बाहर से लाए हुए खाने पर ही निर्भर रहते हैं। जाहिर है बाघ, तेंदुए जैसे कई मांसाहारी जानवरों के खाने भर का मांस जुटा पाना चिड़ियाघरों के प्रशासन के लिए मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह जू में भी शहर के सभी कसाईघरों के बंद होने की वजह से मुसीबतें बढ़ी हैं। प्रशासन को जानवरों के खाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जू के डायरेक्टर आरके सिंह का कहना है कि जू में पहले की तरह संसाधन अब आसानी से उपलब्ध नहीं। जानवरों के लिए जू प्रशासन को कई किलोमीटर दूर से फ्रोजन मीट मंगवा कर देना पड़ रहा है, जो इस वक्त मांसाहारी जानवरों के खाने का अकेला साधन है।

दिल्ली के जू का भी बुरा हाल

राजधानी दिल्ली के चिड़ियाघर में भी यही समस्या थी, जहां गाजीपुर कसाईखाने के बंद होने की वजह से जानवरों को खाने की भारी कमी झेलनी पड़ी। गाजीपुर कसाईखाने में रोजाना करीब 5 हजार जानवरों का वध होता है, जिसमें से बकरी और भेड़ों जैसे करीब एक हजार छोटे जानवरों का मीट अकेले चिड़ियाघर प्रबंधन को ही हर दूसरे या तीसरे दिन सप्लाई होता है। इस कसाईखाने के बंद होने के बाद जानवरों के खाने का इंतजाम करने के लिए जू के अंदर ही मांस का इंतजाम करने के लिए छोटे जानवरों का वध करने की इजाजत लेनी पड़ी। ऐसा सिर्फ दिल्ली के जू का हाल नहीं है, बल्कि देशभर के जू इसी समस्या से जूझ रहे हैं, जिसे लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में एक पीआईएल भी दाखिल हुई है। इसमें लॉकडाउन के बीच कैद जानवरों के खाने और मेडिकल जरूरतों को ध्यान में रख कर और रियायतें देने की अपील की गई है।

नेशनल पार्क में रहने वाले जानवरों की समस्याएं अलग हैं। जंगल के जानवरों की इंसानों पर निर्भरता जू के जानवरों जितनी नहीं होती। लेकिन यहां भी कर्मचारी कई तरह से जानवरों की जिंदगी आसान करने और जंगल में संतुलन बनाए रखने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। काजिरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर पी शिवकुमार कहते हैं कि यहां रहने वाले स्टाफ के पास कुछ वक्त के लिए तो पर्याप्त राशन है, लेकिन उन्हें कुछ स्टाफ के छुट्टी पर होने और आने वाले वक्त में राशन खत्म होने की चिंता है।

कई तरह से इंसानों पर निर्भर हैं जानवर

भारत समेत दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। दुनिया भर में लगे ट्रैवल बैन के जल्द हटने की संभावना भी कम ही है। ऐसे में जिन सेक्टरों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो है पर्यटन। पर्यटन उद्योग के ठप हो जाने का असर जानवरों से जुड़े पर्यटन पर भी होगा और जू या नेशनल पार्कों को सैलानियों से होने वाली आमदनी नहीं होगी। लंबे लॉकडाउन का मतलब होगा नेशनल पार्क और चिड़ियाघरों का घाटा बढ़ेगा और संरक्षण के प्रयासों को झटका लगेगा। ज्यादातर नेशनल पार्क अपने सीजन के दौरान आने वाले पर्यटकों पर अपनी साल भर की कमाई के लिए निर्भर रहते हैं।पर्यटन बिजनेस से नेशवल पार्क और उसके आस-पास के इलाकों के लोगों का रोजगार चलता है। नेशनल पार्क के करीब रहने वाले वहां के रिजॉर्ट्स में, ड्राइवर या टूर गाइड के तौर पर काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। पर्यटकों से आया मुनाफा विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण के लिए इस्तेमाल होता है। टाइगर, बारासिंघा। हाथी और राइनो जैसी प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए साल दर साल कई करोड़ की रकम लगती है, जिसका मूल स्रोत पर्यटन के जरिए आया पैसा है। लेकिन कुछ इलाकों की हालत कोरोना से पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी। काजिरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर पी शि-वकुमार कहते हैं कि इस साल पहले असम में नागरिकता कानून को लेकर हुई हिंसा और उसके बाद अब कोरोना लॉकडाउन में पार्क ने पर्यटन के पीक सीजन के 6 महीने में से 4 महीने का व्यवसाय गंवा दिया। घटते पर्यटन और कम देखरेख के बीच अवैध शिकार की घटनाएं बढ़ने की भी संभावना प्रशासन को परेशान कर रही है। हाल ही में राइनो का शिकार करने की कोशिश में 8 पोचर्स को काजिरंगा नेशनल पार्क के गिरफ्तार किया गया। चीन में राइनो के सींग का इस्तेमाल कोरोना वायरस की दवा बनाने के लिए किए जाने की अफवाहों के बाद काजिरंगा नेशनल पार्क की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।

वायरस से जानवरों को खतरा

कोरोना वायरस मूल रूप से एक जूनॉटिक बीमारी है। यानि ये जानवर से इंसानों में फैली है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये वायरस इंसानों से जानवरों के बीच भी फैल सकता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित ब्रांक्स जू में एक बाघ को कोरोना वायरस होने का पहला मामला कुछ ही दिनों पहले सामने आया। किसी बाघ के कोरोना से संक्रमित होने का ये दुनिया का पहला मामला है। ऐसा माना जा रहा है बाघिन को संक्रमण जू के ही एक कर्मचारी से हुआ है।

इससे पहले भी हांगकांग में दो कुत्ते और बेलजियम में दो बिल्लियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई थीं। यानी फरवरी तक साफ हो गया कि जिसे पहले सिर्फ इंसानों के लिए खतरा माना जा रहा था वो बीमारी जानवरों के लिए भी घातक हो सकती है। लखनऊ जू डायरेक्टर आरके सिंह का कहना है कि वायरस के खतरे से निपटने के लिए पूरे जू को डिसइंफेक्ट किया गया है और साथ ही जू में आईसोलेशन सेंटर की भी व्यवस्था की गई है। वेटेरिनरी डॉक्टर लगातार जू में मौजूद हैं और उनके पास निजी सुरक्षा उपकरण पीपीई भी उपलब्ध है।

ऐसे इंतजाम सिर्फ जू ही नहीं, नेशनल पार्क में भी शुरु हो गए हैं। इस खतरे के बीच भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कार्बेट पहला ऐसा नेशनल पार्क बन गया है जहां जानवरों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क में भी इस तरह के इंतजाम किए गए हैं, पार्क के डायरेक्टर एल कृष्णमूर्ति का कहना है कि पार्क में लगातार वेटेरिनरी डॉक्टर मौजूद हैं और साथ ही आईसोलेशन सेंटर की भी व्यवस्था कर ली गई है। किसी भी जानवर में कोरोनावायरस के लक्षण पाए जाने पर उसे यहां आईसोलेशन में रखा जाएगा। वहीं काजिरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर पी शिवकुमार का कहना है कि जंगली जानवरों में जू में कैद जानवरों से ज्यादा इम्यूनिटी होती है इसलिए कोरोना का खतरा उनके लिए कम है।

जानवरों की जरूरतों की अनदेखी

दुनिया के कुछ सबसे प्रदूषित शहर भारत में हैं। यहां पहली बार वायु गुणवत्ता सूचकांक 0-50 के बीच पहुंचा है, जो शायद बिना लॉकडाउन के असंभव था। यमुना के पानी की क्वालिटी फैक्ट्रियों के बंद होने से बेहतर हुई है। जाहिर है साफ हवा-पानी, घटता प्रदूषण, हर तरफ उड़ती चिड़िया और सड़क पर घूमते जानवर, ये सब देख कर दुनियाभर में कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के फायदों के बारे में लगातार बात हो रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इंसानों के घर में बंद रहने से दुनिया की कई समस्याएं दूर हो गई हैं। खासकर जानवरों के लिए जो अब जंगलों में छुप कर रहने की जगह बाहर निकल रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल कई तस्वीरों में कहीं बैंगलुरू में हाथी घूमते नजर आ रहे हैं, या मुंबई के जंगलों के पास के इलाकों में तेंदुओं के दिखने की बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ हाल ही में वायरल हुआ छत्तीसगढ़ का वीडियो भी है जिसमें डस्टबिन खंगालते भालू नजर आ रहे हैं। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि जानवर किस तरह इंसानों पर कई तरीकों से निर्भर हैं।

कहां से आते हैं नए वायरस?

नाओमी फोरेस्टर

कोरोनावायरसः पहली बात तो यह कि वायरस अचानक किसी अन्य प्रजाति में कूद कर नहीं पहुंच जाता....

कोरोनावायरस के उद्भव ने इस ओर ध्यान खींचा है कि कुछ जोखिम वाले जानवर, मानव के लिए खतरनाक वायरस के स्रोत हो सकते हैं। नोवेल कोरोना वायरस को सार्स-सीओवी-2 के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्रोत चीन के वुहान शहर का वो बाजार बताया गया, जहां जंगली जानवरों का व्यापार होता है। हालांकि, यह पक्का नहीं है कि क्या मानव तक इस वायरस के पहुंचने का जरिया वो बाजार ही था। फिर चमगादड़ की पहचान इस वायरस के वाहक के रूप में की गई। फिर भी, हम यकीनन ये नहीं कह सकते कि चमगादड़ ही सार्स-सीओवी-2 का जनक है।तो सवाल है कि नया वायरस आखिर पर्यावरण से निकला कैसे और कैसे इसने मनुष्यों को संक्रमित करना शुरू कर दिया? समय और प्रक्रिया की बात करें तो, प्रत्येक विषाणु का उद्भव अपने आप में एक अद्वितीय घटना है। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं, जो सभी किस्म के उभरते हुए वायरस प्रजातियों के लिए लागू होते हैं।

पहली बात तो यह है कि वायरस अचानक किसी अन्य प्रजाति में कूद कर नहीं पहुंच जाता। ऐसा होना दुर्लभ है। सफलतापूर्वक किसी अन्य प्रजाति (होस्ट) तक सफलतापूर्वक पहुंचने से पहले वायरस को कई काम करने में सक्षम होना चाहिए।

सबसे पहले, तो वायरस को खुद की संख्या बढाते हुए मेजबान शरीर में संक्रमण पैदा करने में सक्षम होना चाहिए। ज्यादातर वायरस कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं। जैसे, फेफड़े की कोशिकाएं या गुर्दे की कोशिकाएं। कोशिका पर हमला करते समय, वायरस कोशिका की सतह पर विशिष्ट रिसेप्टर अणुओं को बांधता है और इसलिए ये अन्य कोशिकाओं में ये काम करने में सक्षम नहीं हो सकते है। या फिर किन्हीं कारणों से वायरस कोशिका के अंदर खुद की संख्या बढा पाने में असमर्थ हो सकते है। एक बार जब यह एक नए मेजबान को संक्रमित कर लेता है, तो वायरस को खुद की संख्या बढाने में सक्षम होना चाहिए। तभी ये दूसरों को संक्रमित कर सकेगा। ऐसा होना भी बहुत दुर्लभ है और अधिकांश वायरस अपने मेजबान के शरीर में ही खत्म हो जाते है। इसलिए इसे "डेड- एंड होस्ट" भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, इन्फ्लूएंजा वायरस एच5एन1 या बर्ड फ्लू पक्षियों से मनुष्य को संक्रमित कर सकता है, लेकिन मनुष्यों के बीच इसका प्रसार बहुत सीमित है। कभी-कभी एक नया वायरस अपने होस्ट (मेजबान) से नए होस्ट तक पहुंच जाता है और एक नई प्रसार श्रृंखला बना कर महामारी की स्थिति पैदा कर देता है। पिछले कुछ दशकों के शोध से हमने कुछ ऐसे तंत्रों को समझा है, जिसकी वजह से वायरस विभिन्न प्रजातियों के बीच पहुंचता हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस इसका एक शानदार उदाहरण है। वायरस में आठ जीनोम सेगमेंट होते हैं। यदि दो अलग-अलग वायरस एक ही सेल को संक्रमित करते हैं, तो दोनों के सेगमेंट मिल कर एक नॉवेल वायरस प्रजाति बना सकते हैं। यदि नए वायरस की सतह पर पाया जाने वाला प्रोटीन मौजूदा इन्फ्लूएंजा वायरस के मुकाबले बदल जाता है, तो ये आसानी से फैल जाएगा और किसी के पास भी इसके खिलाफ इम्यूनिटी नहीं होगी ।

इन्फ्लूएंजा वायरस में इस बदलाव को एंटीजेनिक शिफ्ट कहा जाता है। 2009 के एच1एन1 इन्फ्लूएंजा महामारी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसी एंटीजेनिक शिफ्ट की वजह से ये सूअरों से मानव तक पहुंचा। इस बात के आनुवांशिक प्रमाण भी हैं कि ऐसा ही मैकेनिज्म कोरोना वायरस के साथ भी काम कर सकता है, हालांकि सार्स-सीओवी-2 के उद्भव में इसकी भूमिका अभी तय होनी बाकी है।

वायरस जीनोम के भीतर आनुवंशिक परिवर्तन की वजह से भी नए वायरस उभर सकते हैं। ये एक आम बात है कि वायरस अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के बजाय रिबोन्यूक्लिक एसिड (आरएनए) में जमा करते हैं। यही कारण है कि ये वायरस (कोरोना वायरस अपवाद है) जब खुद की संख्या बढाते हैं, तब अपनी गलतियों की जांच नहीं कर पाते हैं। वायरस के खुद की संख्या बढाने के दौरान जो परिवर्तन होते है, वे इसके लिए नुकसानदायक होते है। लेकिन कुछ परिवर्तन वायरस को एक नए मेजबान को अधिक प्रभावी ढंग से संक्रमित करने में सक्षम भी बना सकते हैं।

नया कोरोना वायरस

सवाल है कि सार्स-सीओवी-2 के मामले में क्या हुआ? जीनोम के हालिया विश्लेषण से पता चलता है कि वायरस लगभग 40 वर्षों से इसी रूप में घूम रहा था। अभी तक हम जो पहचान कर सके है, उसके मुताबिक ये वायरस चमगादड़ में पाया गया है। हालांकि, कोरोना वायरस और सार्स-सीओवी-2 का लगभग 40 से 70 साल पुराना सहसंबंध है। इसलिए, इस महामारी का कारण ये चमगादड़ वायरस ही हो, जरूरी नहीं है।इन वायरस के बीच एक पुराना सह-संबंध तो है, लेकिन 40 साल के क्रमिक विकास प्रक्रिया ने इन्हें अलग कर दिया है। इसका मतलब यह है कि सार्स-सीओवी-2 चमगादड़ से मनुष्यों तक पहुंचा या किसी अन्य प्रजाति के माध्यम से। उदाहरण के लिए, पैंगोलिन में भी संबंधित वायरस पाए गए हैं। लेकिन आनुवांशिक रूप से सार्स-सीओवी-2 के मनुष्यों तक पहुंचने का सटीक रास्ता तलाश पाना तब तक रहस्य बना रहेगा, जब तक हम पर्यावरण में मौजूद सबसे निकट प्रजाति की तलाश कर पाने में सक्षम नहीं हो जाते। यह भी साफ नहीं है कि वायरस में ऐसे क्या बदलाव हुए, जिससे मनुष्य इतनी आसानी से संक्रमित होते चले गए। हालांकि, यह देखा गया है कि पिछले 20 वर्षों में कोरोनो वायरस परिवार से तीन प्रमुख बीमारियां सामने आई हैं। सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (सार्स), मिडल-इस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (एमईआरएस) और कोविड-19। इस बात की भी संभावना है कि आगे कोरोना वायरस फिर से मनुष्य में पहुंच कर एक नई बीमारी का प्रकोप पैदा कर दे।

इस बात की अधिक संभावना है कि जब ये वायरस दुनिया के सभी जानवरों में पहुंच जाए, तब जानवर और मनुष्य के बीच किसी भी सम्पर्क की वजह से ये केवल मनुष्यों तक पहुंच पाने में ही सक्षम हो। मनुष्य हमेशा नए वायरस के संपर्क में आता रहा है, क्योंकि मानव जाति शुरु से दुनिया भर में नए क्षेत्रों की खोज करता रहा है। वन क्षेत्रों में होने वाली मानव गतिविधि में वृद्धि और जंगली जानवरों का व्यापार इस तरह की महामारी/संक्रमण के लिए एक उर्वर जमीन तैयार करता है।

बढता वैश्विक संबंध भी आज कुछ ही दिनों में एक नई महामारी को दुनिया भर में फैला सकता है। आखिर हमने प्राकृतिक वातावरण को तबाह किया है और इस वजह ने मनुष्य तक वायरस के पहुंचने की संभावना बढा दी है।

फसल वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन के लिए तय किया लक्ष्य

कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 63.5 लाख टन बढ़ाकर 29.83 करोड़ टन करने का लक्ष्य तय किया है।

रिकॉर्ड 29.19 करोड़ टन रह सकता है उत्पादन

मंत्रालय द्वारा फरवरी में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, फसल वर्ष 2019-20 में देश का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 29.19 करोड़ टन रह सकता है। इस संदर्भ में कृषि आयुक्त एसके मल्होत्रा ने खरीफ फसलों की बुवाई की योजना तैयार करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय स्तर के वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि, ''भारत मौसम विभाग का अनुमान है कि जून से सितंबर के दौरान दक्षिण-पश्चिमी मानसून के कारण होने वाली बारिश कुल मिलाकर सामान्य रह सकती है। यह वर्षा पर निर्भर खरीफ फसलों के लिए उम्मीदें बढ़ाता है। मल्होत्रा ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य सरकारों को बताया कि कृषि से जुड़ी गतिविधियों को पाबंदियों से किस तरह की छूट दी गई है।

इतना है लक्ष्य

देश के कुछ हिस्सों में पहले ही खरीफ फसलों की बुवाई शुरू हो चुकी है। फसल वर्ष 2020-21 के दौरान खरीफ सत्र में 14.99 करोड़ टन और रबी सत्र में 14.84 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह पूरे फसल वर्ष 2020-21 के दौरान 29.83 करोड़ टन खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य है।

लॉकडाउन से यमुना को कितनी मिली राहत!

पार्थ कबीर

लॉकडाउन के चलते तमाम गतिविधियों पर लगी रोक से यमुना को भी राहत की सांस मिली है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक यमुना का पानी पिछले साल अप्रैल महीने की तुलना में काफी हद तक साफ हुआ है। समिति ने दिल्ली से गुजरने वाली यमुना में नौ जगहों से नमूने उठाए थे। इन नौ में से चार जगहों पर पानी में बीओडी (बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड) में 18 से लेकर 33 फीसदी तक की कमी आई है। जबकि, यमुना में गिरने वाले नालों का पानी भी पहले की तुलना में साफ हुआ है।

दिल्ली में प्रवेश करने से पहले यमुना नदी अपेक्षाकृत साफ-सुथरी है। लेकिन, यहां पर प्रवेश करने के साथ ही यमुना का पानी बेहद गंदा होने लगता है। यह प्रदूषण इस हद तक है कि नदी के कई हिस्सों में जलीय जीवन का बचे रहना भी संभव नहीं रह गया है। इसी के चलते कुछ लोग यमुना को मृत नदी की संज्ञा भी देने लगे हैं। लेकिन, लॉक-डाउन के चलते इंसानी गतिविधियों पर लगी तमाम प्रकार की रोक से यह साबित होता है कि यमुना में इंसानों का हस्तक्षेप अगर कम से कम हो तो नदी का पानी अभी साफ है और यमुना नदी अभी सदानीरा नदी है। लॉकडाउन के तत्काल बाद यमुना नदी का पानी साफ होने के तमाम दावे किए जा रहे थे। जिसके बाद यमुना निगरानी समिति ने इसकी वास्तविकता की जांच करने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली में नौ जगहों से यमुना के पानी के नमूने उठाए थे। पानी के नमूनों में प्रदूषण की मात्रा की तुलना पिछले साल अप्रैल के महीने में मौजूद पानी के नमूनों से की गई। इससे पता लगा है कि दिल्ली में तमाम जगहों पर यमुना के पानी में आक्सीजन की मात्रा में खासा सुधार हुआ है और यहां पर बीओडी के स्तर में कमी आई है। आगरा कैनाल, ओखला ब्रिज पर 33 प्रतिशत, आईटीओ पुल पर 21 प्रतिशत, ओखला बैराज पर 18 प्रतिशत, निजामुद्दीन ब्रिज पर 20 प्रतिशत और कुदेशिया घाट पर पानी में आक्सीजन की मात्रा में पिछले साल की तुलना चार फीसदी तक का सुधार हुआ है। जान लें कि नदी में प्रदूषण के स्तर को बीओडी के स्तर से मापा जाता है।

बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी आक्सीजन की वह मात्रा है जो किसी माइक्रोआर्गेनिज्म को चाहिए होता ताकि वह किसी कचरा या प्रदूषक को डिकंपोस्ट कर सके। इसलिए बीओडी का स्तर ज्यादा होने का मतलब है कि ज्यादा आक्सीजन की जरूरत है। दूसरी ओर, रिपोर्ट यह भी बताती है कि यमुना के पानी में भी इस वर्ष इजाफा हुआ है। पिछले साल अप्रैल के महीने में यमुना में औसतन एक हजार क्यूसेक पानी मौजूद था। जबकि, इस वर्ष अप्रैल के महीने में 3900 क्यूसेक पानी मौजूद है। इससे भी पानी गुणवत्ता में सुधार आया है।

उद्योग बंद होने से आया बदलाव

यमुना के पानी की गुणवत्ता मे आए सुधार के पीछे मुख्य रूप से औद्योगिक गतिविधियों पर लगी रोक को कारण माना जा रहा है। इस रोक के चलते उद्योगों से निकलने वाला कचरा नदियों में नहीं जा रहा है। इससे यमुना नदी पहले की तुलना में साफ हुई है। हालांकि, अभी इसका पानी ज्यादातर जगहों पर पीने और नहाने लायक नहीं है। क्योंकि, लॉकडाउन के समय में भी घरों से निकलने वाले सीवरेज का बड़ा हिस्सा सीधे इसमें जा रहा है। इससे यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि औद्योगिक कचरे और घरेलू सीवरेज को यमुना में गिरने से रोक लगाए बिना नदी को साफ नहीं किया जा सकता।

रांची मंडल ने 2600 लोगों को भोजन ,राशन सामग्री दिया

रांची : कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए संपूर्ण देश में लॉक डाउन किया गया है, इस परिस्थिति में गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

रांची रेल मंडल द्वारा प्रतिदिन गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन तथा राशन सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। 21अप्रैल को रांची रेल मंडल ने विभिन्न स्थानों पर 2600 गरीब तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन तथा राशन सामग्री का वितरण किया गया ।

मण्डल के कार्मिक विभाग / सर्वो रांची द्वारा भारत स्काउट एंड गाइड के माध्यम से मरहा टोली कल्याणपुर मे राशन सामग्री का वितरित किया गया।

हर एक झारखण्ड वासी का आभारी रहूंगा: हेमंत सोरेन

रांची : मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट में लोगों के सहयोग पर सबों का धन्यवाद किया । आपदा की इस घड़ी हमें सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों, झूठी-भ्रामक खबरों एवं अफवाहों से सचेत रहते हुए एक दूसरे का साथ देना है। आपस में दूरी बनाएं, लेकिन दिलों को जोड़े रखें, इसके लिए मैं सदैव हर एक झारखण्ड वासी का आभारी रहूंगा।

कोरोना संक्रमण से अंगूर किसानों को 17 हजार करोड़ रुपए नुकसान

एजेंसियां :कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव के लिए देश लॉकडाउन में है लेकिन यह समय किसानों पर बेहद भारी बीत रहा है। देश का सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक महाराष्ट्र का किसान इन दिनों परेशान है। अंगूर पैदा करने वाले किसानों के लिए 15 मार्च से 15 अप्रैल की अवधि बेहद खास होती है। अंगूर की हार्वेस्टिंग के लिए यह पीक अवधि है। किसी भी हाल में उन्हें अपने खेतों को खाली करना है। उनका साथ निभाने के लिए लॉक डाउन व पुलिस से भय होने के कारण ट्रांसपोर्ट ठप हैं। किसानों की पैदावार बागों में ही बर्बाद हो रही है। महाराष्ट्र के नासिक में अंगूर किसान इस अवधि में शुरुआती करीब 17 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन कर रहे हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष और कृषि आर्थिक समिति से जुड़े शंकर दरेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के चलते खूब असमय वर्षा हुई है और पहले ही उत्पादन में करीब 30 से 40 फीसदी का नुकसान था। अब कोरोना संक्रमण के फैलाव और भय के बाद अंगूर की सप्लाई नहीं हो पा रही है। मांग सुस्त होने के कारण बाजार भाव भी निचले स्तर पर हैं। हमें इस बंदी से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। भाव न होने के कारण इस बार लागत निकालना भी मुश्किल होगा। हम लोग इस वक्त मजदूरों की अनुपस्थिति में खुद ही ट्रकों में माल लोडिंग के लिए तैयार हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट तैयार नहीं हो रहे। हमारी खेती अगले पांच साल के लिए बर्बाद हो गई है।

बुढमू में वज्रपात से पेड़ में आग लग गयी

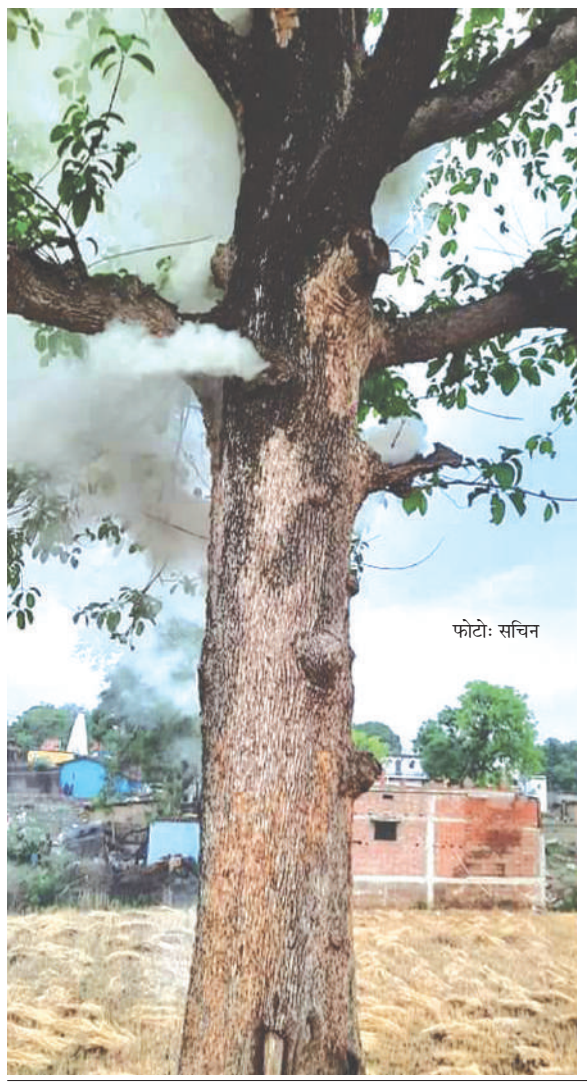

फोटोः सचिन

मुख्यमंत्री ने झारखंड बाजार एप लांच किया

संवाददाता

दो लाख मजदूर हुए निबंधित, जल्द मिलेगी राशि

- मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, विभाग द्वारा तैयार Jharkhand-Bazar एप्प लांच किया
- गूगल प्ले स्टोर से यह एप्प डाउनलोड किया जा सकता है https://bit.ly/34Lm5cC - URL की मदद से भी कर सकते हैं डाउनलोड
- राज्य के लोगों को लॉकडाउन में सुविधा उपलब्ध कराना है लक्ष्य

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन में लोग घरों से बाहर न निकलें और उन्हें खाद्यान्न की आपूर्ति उनके घर तक सुनिश्चित हो। इस निमित नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए झारखण्ड बाजार एप्प लांच किया जा रहा है। एप्प लांच करने का उद्देश्य छोटे-बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को लॉकडाउन में खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। कोरोना जैसे संक्रमण से बचने का कारगर उपाय सामाजिक दूरी का पालन है। ऐसे में यह एप्प राज्य की जनता के लिए कारगर साबित होगा। ये बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री मंत्रालय स्थित सभागार में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, विभाग द्वारा तैयार Jharkhand-Bazar एप्प लांच करने के बाद कही। मुख्यमंत्री ने कहा अर्थव्यवस्था की गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए लॉकडाउन में छूट मिली है। राज्य में केंद्र के आदेश का अनुपालन हो रहा है।

दो लाख श्रमिकों का हुआ निबंधन

मुख्यमंत्री ने बताया कि लॉकडाउन में राज्य के बाहर फंसे श्रमिकों को सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से लांच किये गए मुख्यमंत्री सुविधा एप्प में अब तक करीब दो लाख श्रमिकों ने निबंधन कराया है। सभी श्रमिकों के बैंक खाते में एक हजार रुपये की राशि डीबीटी का माध्यम से डाली जाएगी। एप्प को गूगल प्ले स्टोर में निबंधित करा एप्प की विसंगतियों को दूर कर दिया गया है। राज्य सरकार का प्रयास है कि यहां बसने वाले गरीब, किसान, मजदूर समेत सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

Jharkhand-Bazarएप्प की विशेषता

एप्प को एंड्रॉयड मोबाइल के गूगल प्लेस्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है lhttps://bit.ly/34Lm5cC - URL के माध्यम से भी मोबाइल एप्प को इनस्टॉल कर सकते हैं। एप्प में निबंधन या लॉगिन के बाद एप्प उपभोक्ता के लोकेशन के दो किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले दुकानों की सूची, दुकानदार का नाम और संपर्क नंबर उपलब्ध कराएगा।

एप्प के माध्यम से खाद्यान्न की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से हो सकती है। होम डिलीवरी की सुविधा नहीं होने की स्थिति में एप्प M-pass निर्गत करेगा, जिसकी एक समय अवधि होगी खरीदारी करने की। होम डिलीवरी के लिए भी डिलीवरी करने वाले वाले व्यक्ति का M-Pass निर्गत होगा। हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में यह एप्प कार्य नहीं करेगा

एप के लांचिग के अवसर पर मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री बादल पत्रलेख, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक एमवी राव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बख्शी, मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव, विभिन्न विभागों के सचिव व अन्य उपस्थित थे।

लॉकडाउन में किसानों को बीएयू वैज्ञानिकों का परामर्श

.....पेज 1 का शेष

कटाई एवं थ्रेशिंग करने, चना का दाना दाँत से काटने पर कट आवाज करने पर भंडारण करने एवं कीड़ो से बचाव हेतु सेल्फोस टिकिया या नीम की सुखी पत्ती का उपयोग करने को कहा है।

डॉ अरुण कुमार, पौधा प्रजनक (सरसों) ने सरसों फसल में थोड़ी नमी रहने और प्रातः समय फसल की कटाई करने की बात कही। कटाई के बाद डंडे से पीटकर दौनी व सफाई कर सीड बीन या जुट के बोरे में भंडारित करने की सलाह दी है।

डॉ सोहन राम, पौधा प्रजनक (तीसी) ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में तीसी फसल का प्रदर्शन बेहतर देखने को मिल रहा है और फसल कटाई शुरू हो चुकी है। इस फसल के दाने खेतों में झरते नहीं है। अतिवृष्टि से पौधे के टूटने की संभावना होती है। फसल पककर तैयार होने पर कटाई एवं थ्रेशिंग कर भंडारण करनी चाहिये। इसके दाने में कीड़ो का प्रकोप नहीं होता है।

डॉ सीएस महतो, पौधा प्रजनक (मसूर व मटर) ने बताया कि मसूर व मटर फसल के पकने पर खेतों में ही झरने की संभावना होती है। इन दोनों फसलों के पौधे को हाथ से उखाड़कर खेतों में ही डंडे से पीटकर दौनी करनी चाहिये। 5 प्रतिशत मिलाईथियान घोल से उपचारित बोरा या दाने को स्प्रे कर भंडारण से कीड़ो से बचाव किया जा सकता है।

डायरेक्टर रिसर्च डॉ डीएन सिंह ने रबी फसल के बाद खाली पड़े खेतों में सिंचाई सुविधा होने पर गरमा मकई फसल की बुवाई करने को कहा है। बोई गई गरमा मूंग व गरमा धान के खेत में नमी बनाये रखने, खर-पतवार की निकाई-गुड़ाई करके यूरिया का भूरकाव करने को कहा। उन्होंने खरीफ फसल की खेती में खर-पतवार का नियंत्रण तथा भूमि में मौजूद कीड़ो-मकोड़े व रोग से बचाव हेतु खाली पड़ी उपराऊ, मध्यम एवं नीची भूमि की 2-3 गहरी जुताई करने का परामर्श दिया।

हिरण के बच्चे को वन विभाग में सौंपा

संवाददाता :केरेडारी के घाघरा डैम स्थित जंगल से निकल कर ग्राम पहरा के निर्मल महतो के घर में एक हिरण का बच्चा घुस गया था। जिसे पकड़ कर फॉरेस्ट विभाग को सुपुर्द कर दिया गया।

सीएमपीडीआई में डॉ0 भीम राव अम्बेदकर की जयंती मनायी गयी

संवाददाता

रांची: 14 अप्रैल को सीएमपीडीआई मुख्यालय में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए एक संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित कर ''भारत रत्न'' बाबा साहब डॉ0 भीम राव अम्बेदकर की जयंती मनायी । इस मौके पर संस्थान के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एस0 सरन ने कहा कि भले ही एक संक्षिप्त कार्यक्रम के माध्यम से बाबा साहब की जयंती मनायी जा रही है किन्तु उनके जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे साल भर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

एस0 सरन ने कहा कि बाबा साहब युगपुरूष, संविधान निर्माता थे। वो वृहत गणतंत्र प्राप्त करने में हमेशा प्रयासरत रहे। हमारे संविधान में मानवीय पक्ष का जो समावेश किया गया है, वह दुनिया के कई देशों में समाहित नहीं किया गया है। यह हमारे संविधान की सुन्दरता है। अपने समय के राजनेताओं में उनकी गिनती विद्वान एवं मेधावी नेता के रूप में होती थी। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई पुरानी परंपरा एवं सभ्यताएं समाप्त हो गयीं। किन्तु हमारी परंपरा एवं सभ्यताएं आज भी जीवंत है।

इसके पूर्व संस्थान के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एस0 सरन, निदेशक आर0एन0 झा, निदेशक एस0के0 गोमास्ता, महाप्रबंधक श्रीमती सुनीता मेहता ने दीप प्रज्जवलित कर इस समा-रोह की शुरूआत की एवं बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर सर्वेश प्रसाद, सिस्टा काउंसिल के प्रतिनिधि गोरेलाल पासवान एवं अन्य ने अपने विचार प्रकट किए स्वागत भाषण एवं मंच संचालन नवीन कुमार सिन्हा तथा सुनीता मेहता ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

आदेश के बाद भी नहीं हो रही बिहार में गेहूं की खरीदादारी

संवाददाता

कैमूर, बक्सर, सारण, सीतामढ़ी, मधेपुरा समेत एकदम दर्जन जिलों के किसानों का कहना है कि यहां सरकारी स्तर पर गेहूं की खरीद शुरू नहीं हुई है। वैशाली के किसान यूके शर्मा को इस बार 65 क्विंटल गेहूं हुआ है। गेहूं की कटाई से लेकर दौनी तक वह 32000 रुपए खर्च कर चुके हैं। इनमें से 25000 रुपए ही वह दे पाए हैं, 7000 रुपए देना अभी बाकी है। यूके शर्मा ने बताया, "मैंने सोचा था कि सरकारी स्तर पर गेहूं की खरीद शुरू होगी, तो गेहूं बेचकर बाकी 7000 रुपए का भुगतान कर दूंगा, लेकिन अब तक गेहूं की खरीद शुरू नहीं हुई है।

हालांकि, खुले बाजार में कुछ व्यापारी गेहूं खरीदने को तैयार हैं, लेकिन कीमत कम मिल रही है। यूके शर्मा ने कहा, "बाजार में व्यापारी 1600-1800 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा देने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में घाटा सह कर भला कैसे गेहूं बेच दें? इस बार वैसे भी बेमौसम बारिश के कारण उत्पादन 30-40 प्रतिशत घट गया है।" बिहार सरकार ने 15 अप्रैल से प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (पैक्स) के जरिए राज्य भर में गेहूं की खरीद शुरू करने की घोषणा की है। कैमूर, बक्सर, सारण, सीतामढ़ी, मधेपुरा के किसानों ने कहा कि उनके यहां सरकारी स्तर पर गेहूं की खरीद शुरू नहीं हुई है। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एफबीआई) के आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं। एफसीआई ने मौजूदा साल में अब तक (17 अप्रैल तक) गेहूं की खरीद का जो आंकड़ा पेश किया है, उसके मुताबिक, पंजाब, यूपी, एमपी और राजस्थान में गेहूं की खरीद चल रही है, लेकिन बिहार में शून्य खरीद हुई है।

मुजफ्फरपुर के किसान तेजनंदन ठाकुर ने इस बार डेढ़ बीघा में गेहूं की खेती की थी। उन्होंने बताया, "इस बार लगभग 12 क्विंटल गेहूं हुआ है, लेकिन यहां पैक्स के जरिए गेहूं की खरीद अभी शुरू नहीं हुई है। फिलहाल गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने का इंतजार करने के सिवा कोई उपाय नहीं है। गौरतलब है कि बिहार में 8 हजार से कुछ ज्यादा पैक्स हैं, जो बिहार की आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से कम है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं, जिनके लिए खरीद केंद्र तक पहुंचना मुश्किल काम है। वहीं, हाल के कुछ वर्षों में बिहार में गेहूं खरीद केंद्रों में भी गिरावट आई है। बताया जाता है कि साल 2015-2016 में बिहार में गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या 9000 से अधिक थी, जो घटकर 7000 रह गई। खरीद केंद्र कम होने, देर से सरकारी खरीद और जटिल प्रक्रिया के कारण बहुत किसान ऐसे भी हैं, जो खरीद केंद्रों में जाने के बजाय कम कीमत पर स्थानीय व्यापारियों को गेहूं बेचना पसंद करते हैं।पटना के बाढ़ प्रखंड के किसान सत्येंद्र सिंह ने बताया, कि हमलोग नून-तेल जैसी घरेलू जरूरतें अनाज बेचकर पूरी करते हैं। सरकारी खरीद शुरू नहीं होने के चलते मुझे 1800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 10 क्विंटल गेहूं बनियों को बेचना पड़ा। पैक्स तक पहुंचने और गेहूं बेचने में हजार तरह की दिक्कतें हैं। कौन इस झमेले में पड़े ?वहीं पैक्स अध्यक्षों ने लाकडाउन के साथ ही सरकार पर बकाया राशि का भुगतान नहीं होने को जिम्मेदार ठहराया। मोकामा के एक पैक्स के अध्यक्ष ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा, "पिछले साल का पैसा सरकार पर बाकी है। सरकार ने पैसा नहीं दिया, हमलोग किसानों को भी नहीं दे पाए। इस वजह से किसानों को पैक्स पर भरोसा नहीं है। दूसरी वजह ये है कि लाकडाउन के कारण किसान खरीद केंद्र तक आने से कतरा रहे हैं।" उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने पैक्स के जरिए गेहूं खरीद की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई लिखित आदेश उन तक नहीं पहुंचा है।

गेहूं खरीद के आंकड़े भी बताते हैं कि किसान सरकार को गेहूं बेचना नहीं चाहते है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2018-2019 में बिहार में जितना गेहूं का उत्पादन हुआ था, उसका महज 0.29 प्रतिशत हिस्सा ही सरकार खरीद पाई थी जबकि साल 2019-2020 में महज 0.05 फीसद गेहूं की ही सरकारी खरीद हुई थी। एफसीआई से मिले आंकड़े बताते हैं कि साल 2019-2020 में बिहार से महज 0.03 लाख मीट्रिक टन गेहूं की ही अधिप्राप्ति हो पाई थी, जो एक दर्जन शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्यों में हिमाचल प्रदेश के सभी बाद सबसे कम था।

मुम्बई के एक प्राइवेट कंपनी से निकाले गये 30 मजदूरों के रहने एवं खाने की की गई व्यवस्था

संवाददाता रांचीः विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के संक्रमण से देश में 3 मई तक चलने वाले लॉक डाउन के वजह से झारखंड राज्य के कई लोग राज्य के बाहर फंसे हुए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि उनकी सहायता के लिए हम प्रतिबद्ध है। झा-रखंड के सभी जिलों में जिला प्रश-ासन द्वारा अपने स्तर पर हर संभव सहायता की जा रही है। इसी क्रम में गिरिडीह जिला के 30 मजदूरों को मुंबई के रायगढ़ के एक प्राइवेट कंपनी द्वारा कंपनी से निकाल देने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके कारण वे लोग भूखे रह रहें थे। इसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरिडीह जिला नियंत्रण कक्ष के द्वारा मुंबई एवं रायगढ़ के नियंत्रण कक्ष से संपर्क स्थापित किया गया। रायगढ़ प्रशासन द्वारा उक्त कंपनी को निर्देशित किया गया कि सभी 30 मजदूरों के रहने एवं खाने की व्यवस्था की जाए। मौके पर पहुंच कर महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा उन सभी मजदूरों को रहने और खाने सहित अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई गई। श्रम विभाग से प्राप्त आंकड़ो के अनुसार अब तक झारखंड के बाहर अन्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 12,696 जगहों पर 6,08,086 प्रवासी मजदूरों के फंसे होने की जानकारी प्राप्त हुई है। अब तक स-रकार द्वारा 10,754 जगहों पर फंसे 4,56,116 मजदूरों के खाने एवं रहने की व्यवस्था की गयी है। सभी लोगों के संबंध में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि उन तक हर स्तर से मदद पहुंचाई जा सके।

आम के पेड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए करें छिड़काव

किसानों के लिए जरूरी जानकारी

एजेंसियां:चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के उद्यान विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी ने लॉक डाउन के दौरान आम के बाग में कीड़ों से बचाव के लिए सोमवार को एडवाइजरी की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष माह जनवरी तक अधिक ठंड पड़ने के कारण आम में वृक्षों में बौर देर से व कम आए हैं। साथ ही कुछ क्षेत्रों में मार्च माह में ओलावृष्टि व तेज हवाओं के कारण आम की फसल को काफी क्षति हुई है। डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि आम के पेड़ों पर मटर के दानों से भी बड़े फल बन चुके हैं। इस समय तरह-तरह के कीटों से फसल को बचाने के लिए दवाओं का छिड़काव व कुशल प्रबंधन से अच्छी पैदावार हो सकती है।

भुनगा कीट : रोकथाम के लिए थाईमैथकजाम

25 डब्ल्यू जी की एक ग्राम मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर पौधों पर छि-ड़काव करें। स्केल कीट : सफेद रंग का यह कीट टहनियों, बौरे एवं फलों में चिपक कर रस चूसता है। इसके नियंत्रण के लिए डाईमेंथोएट 30 ईसी की दो मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर पत्तियों, शाखाओं और बौरे पर छिड़काव करना चाहिए।

खर्रा रोग : रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल 50 रछ की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना चाहिए। एंथक्नोज रोग : कार्बेंडाजिम 50 हढ की एक ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करने से फसल को बचाया जा सकता है।

फलों के झड़ने पर : बागवान प्लानओंफिक्स 4.5% की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव से समस्या दूर हो होगी।

सलाह : डॉक्टर त्रिपाठी ने आवश्यकतानुसार के मुताबिक सिंचाई और फलों की अच्छी वृद्धि के लिए घुलनशील उर्वरक 19: 19: 19 के पांच ग्राम और सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण के पांच ग्राम को प्रति लीटर पानी की दर से घोल कर छिड़काव लाभ प्रद होगा। डॉक्टर खलील खान ने बागवानों से अपील की है कि आम के बागों में कार्य करते समय मुंह पर मास्क लगाएं व सामाजिक दूरी अवश्य बनाए रखें ।

नदियां अविरल रहें तो वो खुद अपनी सफाई कर लेती हैं

राहुल कोटियाल

इन दिनों गंगा-यमुना का पानी स्वतः ही बेहद साफ नजर आने लगा है। दिल्ली तक आते-आते जो यमुना पूरी तरह से गंदा नाला दिखने लगती है, इन दिनों फिर से नदी लगने लगी है। ऐसे ही गंगा भी इन दिनों इतनी साफ लगने लगी है कि ऋषिकेश-हरिद्वार तक तो उसके पानी को पीने योग्य बताया जाने लगा है।

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हालिया रिपोर्ट बताती है कि ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में इन दिनों गंगा के पानी में फ़ीकल कॉलिफोर्म (मानव मल) की मात्रा में 47 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं ऋषिकेश में बैराज से आगे यह कमी 46 प्रतिशत, हरिद्वार में बिंदुघाट के पास 25 प्रतिशत और हर की पौड़ी पर 34 प्रतिशत दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है लॉकडाउन के दौरान हर की पौड़ी पा गंगा का पानी 'क्लास-ए' स्तर का हो चुका है। यानी इसे ट्रीट किए बिना ही सिर्फ़ क्लॉरिनेशन करके भी पिया जा सकता है। ऐसे में यह सवाल बेहद प्रासंगिक लगता है कि गंगा-यमुना सफ़ाई के नाम पर खर्च हो चुके हज़ारों करोड़ रुपए और तमाम सरकारी प्रयास जो नहीं कर सके, क्या लॉकडाउन ने नदियों को साफ करने का वो काम कर दिया है? इस सवाल के जवाब में 'इंडिया वॉटर पोर्टल' के संपादक केसर सिराज कहते हैं, 'काफ़ी हद तक किया है। लेकिन इसके कई पहलू हैं। नदी के प्रदूषित होने के कई कारण हैं। ये कारण शहरों में अलग हैं और पहाड़ों में अलग। इनमें सबसे बड़े कारण कारख़ानों से निकलने वाले रसायनों का नदी में मिलना है और दूसरा बिना ट्रीट हुए मानव मल का इनमें मिलना। इन दिनों चूंकि पूरे देश में कारख़ाने हैं लिहाज़ा पानी का स्तर कुछ बेहतर हुआ है।'

सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के डेटा के मुताबिक गंगा नदी के 36 मॉनिटरिंग यूनिट हैं जिनमें से 27 पर पानी नहाने और वाइल्ड लाइफ और फिशरीज के लिहाज से सुरक्षित है। हरिद्वार में स्थित 'मातृ सदन' गंगा को बचाने के लिए बीते कई दशकों से अभियान चला रहा है। इस अभियान में सदन से जुड़े स्वामी निगमानंद और प्रोफ़ेसर जीडी अग्रवाल समेत कई लोगों ने तो अपने प्राण तक त्याग दिए हैं। इस सदन के प्रमुख स्वामी शिवानंद कहते हैं, 'लॉक-डाउन के बाद गंगा का पानी कुछ हद तक साफ हुआ है। इससे एक बात तो यही स्पष्ट होती है कि स-रकार जो दावा करती है कि हरिद्वार से ऊपर सिर्फ़ ट्रीट किया हुआ सीवेज ही गंगा में मिलता है, वह दावा झूठा है। इन दिनों क्योंकि यात्रा बंद है, पहाड़ पर पर्यटकों की भरमार नहीं है इसलिए अंट्रीटेड सीवेज गंगा में नहीं जा रहा और तभी ये पानी साफ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हरिद्वार में गंगा का पानी पीने लायक़ नहीं हुआ है। हम गंगा किनारे रहते हैं, इसलिए ये बात दावे से कह सकते हैं। स्वामी शिवानंद कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं का भी ज़िक्र करते हैं। वे कहते हैं, 'गंगा या यमुना को एक पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो ख़ुद को साफ करने में सक्षम

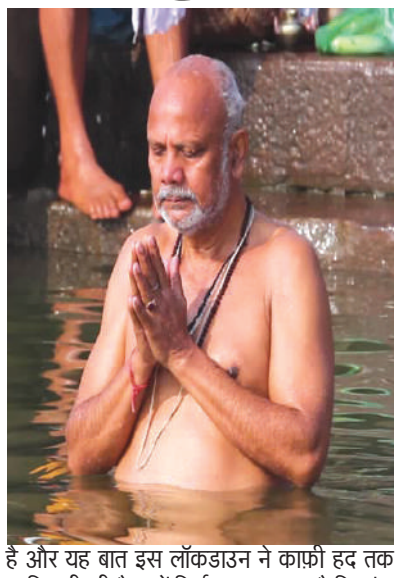

है और यह बात इस लॉकडाउन ने काफ़ी हद तक साबित भी की है। हमें सिर्फ़ इतना करना है कि गंगा की अविरलता को बने रहने दिया जाए। लेकिन आप देखिए कि हरिद्वार पहुँचने से पहले ही गंगा को सैकड़ों जगह बांध दिया गया है। अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी जैसी गंगा की सभी धाराओं पर डैम बना दिए गए हैं तो उसकी अविरलता तो वहीं बाधित हो चुकी है। ऐसे में गंगा ख़ुद को साफ कैसे करेगी जब उसका प्रवाह ही रोक दिया जाएगा।गंगा के मुक़ाबले यमुना इस लिहाज़ से ख़ुशक़िस्मत है कि उस पर जल विद्युत परियोजनाओं का ऐसा बोझ नहीं है। लेकिन यमुना जैसे ही पहाड़ों से मैदान में पहुँचती है, इसकी हत्या शुरू हो जाती है। डाक पत्थर नाम की जगह से ही यमुना पर बैराजों और नहरों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि यमुना के नाम पर बसे यमुनानगर तक पहुँचने से पहले ही यमुना पूरी तरह मर चुकी होती है। इसकी मुख्यधारा का लगभग पूरा पानी नहरों में मोड़ दिया जाता है और तब सिर्फ़ कुछ नालों, बरसाती नदियों और छोटी-बड़ी धाराओं के साथ फैक्ट्रियों की गंदगी लिए जो कथित नदी आगे बढ़ती है, वह सिर्फ़ नाम की ही यमुना होती है।उफनते नाले सी दिखने वाली यमुना नदी शायद पहली बार नीले साफ पानी से लबालब नजर आई है, पहली बार यहां प्रवासी पक्षी और मछलियां दिखाई दी हैं। साल 2000 में आई सीएजी की एक रिपोर्ट बताती है कि 1985 में शुरू हुआ 'गंगा ऐक्शन प्लान' 15 सालों में क़रीब 902 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अपना ये उद्देश्य पूरा नहीं कर पाया कि गंगा के पानी को नहाने लायक़ भी साफ किया जा सके। लगभग यही स्थित 'यमुना ऐक्शन प्लान' की भी है जिसके तीन चरणों में अब तक 1656 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और नतीजा दिल्ली में बदबू मारती यमुना के रूप में सबके सामने है।

यमुना जिये अभियान से जुड़े मनोज मिश्रा एक लेख में बताते हैं कि इतने सालों तक गंगा और यमुना सफ़ाई के नाम पर कारख़ानों से निकलने वाले रसायनों को अनदेखा किया गया जबकि ज़्यादा ध्यान सीवेज ट्रीटमेंट पर दिया गया। इन दिनों भी सीवेज तो हमेशा की तरह नदी में जा ही रहा है लेकिन कारख़ाने पूरी तरह बंद हैं और नदियों में पानी काफ़ी साफ दिख रहा है। इससे समझा जा सकता है कि नदियों को दूषित करने का बड़ा कारण क्या रहा है।

मनोज मिश्रा इस तथ्य पर भी ध्यान दिलाते हैं कि इस साल अच्छी वर्षा होने के कारण नदियों में पानी ज़्यादा छोड़ा गया है। यह भी एक बड़ी वजह है कि लॉकडाउन के दौरान नदियाँ साफ दिख रही हैं क्योंकि उनमें प्रवाह ज़्यादा है।

स्वामी शिवानंद कहते हैं, 'गंगा हो यमुना हो या कोई भी नदी हो, उसमें ख़ुद को साफ रखने की क्षमता होती है। इन नदियों ने ही सभ्यताएं बसाई हैं, सभ्यताओं ने नदियाँ नहीं। नदी को साफ़ करने की बात कहना सिर्फ़ ढोंग है और इस देश में तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खेल है। नदियों को बस उनके प्राकृतिक बहाव के साथ अविरल बहने दिया जाए, बड़े बांध बनाकर उनका प्रवाह न रोका जाए, कारख़ानों और मानव मल के सीवेज उनमें न छोड़े जाएँ, वो ख़ुद ही साफ रह लेंगी रहेंगी और हम सबको जीवन भी देती रहेंगी। जिन्हें ये बात पहले नहीं समझ आती थी, इस लॉकडाउन में मिली झलक से समझ सकते हैं। नदियों को सफ़ाई के लिए पैसों की नहीं, नीयत की ज़रूरत है।

प्रत्येक भोपाल गैस पीड़ित की करनी होगी कोविड-19 जांचः हाईकोर्ट

भोपाल गैस पीड़ित संगठनों के वकील ने कोर्ट को बताया कि अब तक भोपाल में कोविड-19 से मौतें हुई हैं वो सभी गैस पीड़ित हैं, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में इलाज कराने जाने वाले गैस पीड़ितों की अब कोविड-19 की जांच भी की जाएगी। यह आदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने को गैस पीड़ित संगठनों की रिट याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जज विजय कुमार शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की। गैस पीड़तों के संगठन भोपाल फोर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन ने सह याचिकाकर्ता मुन्नी बी के साथ कोर्ट में उन आदेशों को रद्द करने के लिए याचिका लगाई थी जिसमें मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बी एमएचआरसी को केवल कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए चिन्हित किया था ।

फोटो न्यूज

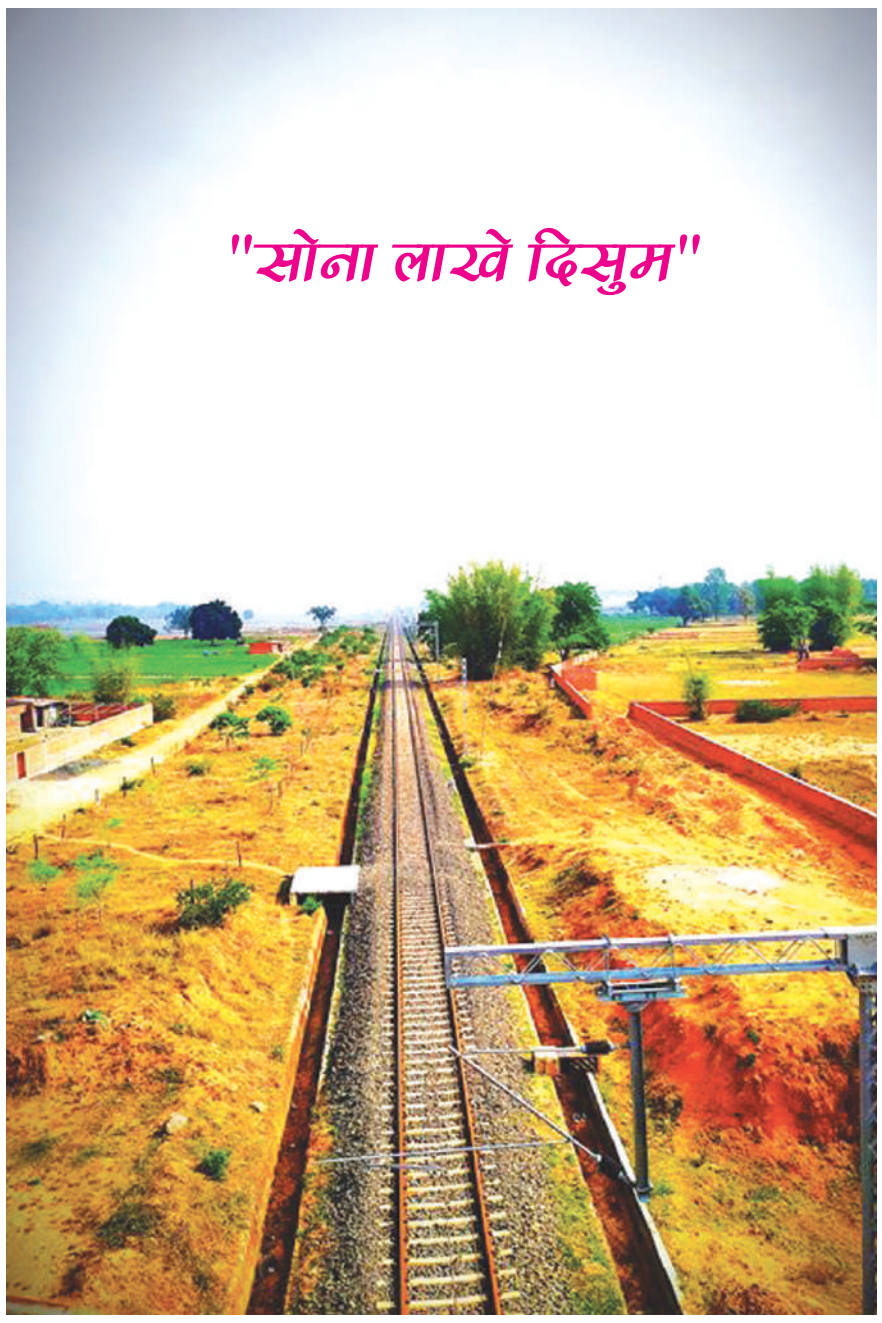

रुक सा गया देश की पटरी पर विकास नामक रेलगाड़ी फिर प्रकृति ने ली करवट झूम उठे पेड़ लहलहा उठे खेत

ये फोटो क्लिक स्वतंत्र पत्रकार सचिन दास गोस्वामी ने चुटु से गुजर रहे रेल ट्रैक पर ली है

फलों और सब्जियों में छुपा है सेहत का खज़ाना

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

फलों और सब्जियों में जरूरी न्यूट्रीएंट्स होते हैं जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। इनमें बीटा-कैरोटीन जिसे विटामिन अ के नाम से जाना जाता है, विटामिन उ, विटामिन ए, मैग्नीशियम, जिंक, फोसफोरस और फोलरिक एसिड होता है।ये हमारे इम्युन सिस्टम को मजबूत करता है और खतरनाक बिमारियों से बचाता है। फलों और सब्जियों के खाने से डायबिटीज, अस्थमा, हृदय रोग, अर्थराइटिस, अल्जाइमर, तनाव, पहृउ निर्माण, एंटी एजिंग आदि में सहायक है।फल और सब्जियां फाइबर से भरपूर होती है जिससे वज़न कम होता है , ये दांतों के लिए भी फायदेमंद है।जब हम फलों और सब्जियों को चबा कर खाते हैं तो दांतों का एक्सरसाइज तो होता ही है और उसके साथ उसे पोषक तत्व भी मिलता है।फल और सब्जियां फाइबर से भरपूर होती है जिससे वज़न कम होता है ।हमें रोज के भोजन में फल और सब्जियों भरपूर मात्रा में खानी चाहिए।हमेशा फल और सब्जियों मौसम के हिसाब से ही खानी चाहिए ।एक तो मौसमी फल और सब्जियों ताज़ा होती है और हमें मौसम के हिसाब से इसका लाभ भी ज्यादा होता है।

कच्चे फल और सब्जियों में न्युट्रशन ज्यादा मात्रा में होता है। मैं कुछ रेसिपी शेयर करती हूं जो टेस्टी और हेल्दी भी है।

टेस्टी सलाद

सामग्री-

1खीरा
1टमाटर
1प्याज
1मूली
1चम्मच निंबू का रस/एक बाउल दही
2 हरी मिर्च
1टी स्पून चाट मसाला
1टी स्पून मिर्च पाउडर
नमक स्वादानुसार

सभी सब्जियों को धोकर फिर उन्हें लम्बा या गोल अपने हिसाब से काट लें अब इसके ऊपर सभी सामग्री को अच्छे से मिलाएं और आपका टेस्टी और हेल्दी सलाद तैयार है। अगर आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नींबू का प्रयोग न करें।

फल की स्मूदी

सामग्री-

1सेब/केला/आम/मिक्स फल
1 कप दूध
1/2 कप दही
शहद/खजूर
बादाम 4-5 (भींगे हुए)

सारे सामग्री को ब्लेन्डर में ब्लेड करें और आपकी स्मूदी तैयार है।

पालक की स्मूदी

सामग्री-

1 कप प्लेन सोया मिल्क
3/4 कप ताज़ा पालक के पत्ते
एक केला

सोया मिल्क और पालक के पत्तों को अच्छे से ब्लेड करें फिर बाद में केला डाल कर एक बार फिर से बेलेनडर चलाये। पालक स्मूदी तैयार है।

इस तरह से आप अपना मनपसंद स्मूदी तैयार कर सकते हैं।

जर्मनी में चीड़ियाघर प्रबंधन का पशुओं के प्रति क्रूर फैसला

एजेंसियां : कोरोना महामारी में पर्यावरण के सुधरने की चर्चा तो सभी कर रहे हैं, पर जर्मनी में इसका एक एक दुखद पहलू भी सामने देखने को मिल रहा है। वहां के एक चीड़ियाघर में कोरोना संकट के चलते लोगों का आना बंद हो गया इस कारण से जू की कमाई भी बंद हो गयी और जानवरों के खाने पर संकट आ पड़ा। ऐसी स्थिति में चीड़ियाघर प्रबंधन ने एक बहुत ही क्रूर फैसला लिया है। अब वहीं के शाकाहारी जानवरों को मार कर उनका मांस चीड़िया घर के मांसाहारी जीवों को खिलाया जायेगा। प्रबंधन का कहना है कि यहां शाकाहारी जीवों में हिरणों की संख्या काफी है जिन्हें मारा जायेगा।

आठ लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुये पहुंचे

एजेंसियां : ओड़िशा के समुद्र तट पर इस बार अंडे देने के लिए सात लाख नब्बे हजार ओलिव रिडले कछुए पहुंचे हैं। अगर इसे कोरोना का असर कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरों को देखते हुए देश भर में लॉक डाउन कर दिया गया है। इससे पॉल्यूशन लेवल काफी कम हुआ है। साथ ही समुद्री जीवन में भी बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। ओड़िशा के तट पर इस बार सात लाख नब्बे हजार ओलिव रिडले कछुए पहुंचे हैं। इन्होंने अपने संघर्ष का युद्ध मानो जीत लिया है। अपने समुद्र में अपना कब्जा हो गया है। इन कछुओं ने गहिरमाथा और रूसीकुल्य में छह करोड़ से ज्यादा अंडे दिए हैं।

बता दें कि कोरोना वायरस के चलते मछुआरों और टूरिस्टों की गतिविधि ठप पड़ी है। माना जा रहा है कि इसी के चलते इतनी बड़ी संख्या में इस बार कछुए पहुंच सके हैं। जंगलकथा विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर इंसानों की गतिविधियां सीमित नहीं होती तो इनमें से बहुत सारे रास्ते में ही मारे जाते या फिर अन्य बाधाओं के चलते पहुंच ही नहीं पाते। ये गतिविधियां पिछले पांच दिनों के दौरान की हैं, जब ओडिशा के गंजाम जिले के 6 किलोमीटर लंबे रुशिकुल्या समुद्र तट पर बड़े पैमाने पर घोंसले के शिकार के लिए ओलिव रिडले समुद्री कछुए आए हैं। बेरहमपुर डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर , अमलान नायक ने बताया कि 22 मार्च को लगभग 2 बजे, 2,000 मादा ओलिव रिडलो कछुये समुद्र से समुद्र तट से बाहर निकलने लगीं। ऐसा माना जाता है कि मादा कछुए उसी समुद्र तट पर वापस लौटती हैं जहां उन्होंने अंडे दिए थे।

इस लिहाज से ओडिशा का तट उनके लिए सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला बनाने वाली जगह है।

रिपोर्ट के अनुसार मानव घुसपैठ और तट पर कचरे के ढेर ने उन्हें 2019 में घोंसले से दूर रखा था। वन विभाग के अनुसार, 2,78,502 से अधिक मां कछुए दिन-प्रतिदिन की घोंसले की गतिविधि का एक हिस्सा बन गए। मंगलवार की सुबह से 72,142 से अधिक ओलिव रिडले घोंसले खोदने और अंडे देने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे हैं।

लॉकडाउन के बाद क्या होगा?

देवाशीष

कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी को पर्यावरण में बदलाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अभी सब कुछ बंद है, तो कार्बन उत्सर्जन रुक गया है। लेकिन जब दुनिया फिर से पहले की तरह चलने लगी तो क्या ये कार्बन उत्सर्जन फिर से नहीं बढ़ेगा? पर्यावरण में जो बदलाव हम आज देख रहे हैं क्या वो हमेशा के लिए स्थिर हो जाएंगे।

स्वीडन के एक जानकार और रिसर्चर किम्बर्ले निकोलस के मुताबिक़, दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का 23 फ़ीसद परिवहन से निकलता है। इनमें से भी निजी गाड़ियों और हवाई जहाज़ की वजह से दुनिया भर में 72 फीसद कार्बन उत्सर्जन होता है। अभी लोग घरों में बंद हैं। ऑफिस का काम भी घर से कर रहे हैं। अपने परिवार और दोस्तों को वक़्त दे पा रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में हो सकता है लोग इसकी अहमियत समझें और बेवजह गाड़ी लेकर घर से निकलने से बचें। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा पर्यावरण के हालात थोड़े परिवर्तन के साथ लंबे समय तक चल सकते हैं। वही निकोलस ये भी कहते हैं कि बहुत से लोगों के लिए हर रोज़ ऑफिस आना और दिल लगाकर काम करना ही ज़िंदगी का मक़सद होता है। इस दिनों उन्हें घर में बैठना बिल्कुल नहीं भा रहा होगा। वो इस लॉकडाउन को क़ैद की तरह देख रहे होंगे। हो सकता है वो अभी ये प्लानिंग ही कर रहे हों कि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा वो फिर से कहीं घूमने निकलेंगे। लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत जल्द दुनिया की आब–ओ–हवा में ज़हर घुलने लगेगा।

घरों से लुप्त होने लगे हैं लकड़ी के बर्तन

डॉ. मोहन पहाड़ी

पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में लकड़ी के बर्तनों का उपयोग लगभग बंद हो गया है। कभी दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले लकड़ी के इन बर्तनों के नाम तक आज की पीढ़ी नहीं जानती होगी।

लकड़ी के बने इन बर्तनों का प्रयोग अधिकांशतः दूध और उससे बनने वाली वस्तुओं को रखने के लिये किया जाता था। जिसका कारण लम्बे समय तक वस्तु का अपनी गुणवत्ता बनाये रखना है। लकड़ी के इन बर्तनों को बनाने के लिये मुख्य रूप से ऐसी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है जो वर्षों पानी में रहने के बाद भी नहीं सड़ती हैं।

गहराई और उपयोग के आधार पर इन्हें अलग-अलग नाम दिये गए हैं। कटोरे के जैसे चौड़े मुख और कम गहराई वाले लकड़ी के बर्तन को कठ्यूड़ी कहा जाता है। कठ्यूड़ी का उपयोग मक्खन, चटनी आदि रखने में किया जाता है। कठ्यूड़ी के जैसा ही देखने वाला एक और बर्तन होता है पाल्ली। पाल्ली, कठ्यूड़ी से अधिक गहरा होता है। इसमें तीन चार लीटर से सात आठ लीटर तक दूध या अन्य पदार्थ भरा जा सकता है। हड़प्या, समतल आधार और बाहर की ओर उभरी दीवारों वाले कम ऊंचाई के लकड़ी के बर्तन हैं। इसी आकार में जिनकी ऊंचाई अधिक होती है उसे ठेकी कहते हैं। ठेकी में दही जामाया जाता है उसमें दही मथकर छांछ भी बनायी जाती है। हड़प्या घी रखने के लिये प्रयोग में लाया जाता है।

घड़े के समान संकरी गरदन वाले डेढ़ दो लीटर धारिता वाले बर्तन पारी कहलाते हैं। वहीं तीनचार लीटर धारिता वाला पारा और इससे अधिक धारिता वाला बर्तन बिंडा कहलाता है। पारा और बिंडा सामान्य रूप से बिना ढक्कन वाले ही बनते हैं। इनका प्रयोग भी दूध दही इत्यादि रखने के लिये किया जाता है। बिंडा मुख्य रूप से दही मथकर छांछ बनाने में प्रयोग किया जाता है। पारी के आकार के ढक्कनदार बर्तन को चाड़ी और कुमली नाम से जाना जाता है। इनका प्रयोग दूध और दही के उत्पादों के इधर-उधर ले जाने के लिये किया जाता है।

नाली और माना अनाज के लेन-देन के लिये बनाये गए लकड़ी के बर्तन हैं। पशुओं को पानी पिलाने के लिये दूना बनाया गया है। इसकी धारिता आठ से दस लीटर तक होती है। लकड़ी से बने इन बर्तनों में दूना और पाल्ली ही ऐसे हैं जिन्हें बासुले से छिल कर बहुउपयोगी बनाया जाता है।

सुग्गों की मोहक तस्वीर :हमीन हकी नगपुरिया के फेसबुक वाल से

कोरोना महामारी से लॉकडाउन में भी जारी है अमेजन जंगलो की बर्बादी

कोविड-19 में भी नहीं सुधरे लोग, अमेजन के जंगलों में तेज कर दी कटाई, क्या होगा दुनिया का?

एजेंसियां :एक तरफ पूरी दुनिया में लॉकडाउन है तो दूसरी तरफ़ दुनिया के सबसे बड़े रेनफॉरेस्ट अमेजन के जंगल में पेड़ों का कटाव जारी है। ब्राजील नेशनल स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट (क्छढए) की रिपोर्ट के मुताबिक़, इन दिनों जंगल में पेड़ों का कटाव अप्रैल 2008 के बाद सबसे ज्यादा है। डिफॉरेस्टेशन मॉनिटरिंग सिस्टम के डेटा के मुताबिक़, सिर्फ़ मार्च के महीने में वहां 327 स्कवायर किमी क्षेत्र में पेड़ों का कटाव हो गया। यह पिछले साल 9152 स्क्वायर किमी से आगे बढ़ता दिख रहा है। 12 महीने के पीरियड का अभीतक अधिकम मई 2008 का है जब 9190 स्क्वायर किमी क्षेत्र का डिफॉरेस्टेशन हुआ था।

ये नया डेटा इसलिए भी डराता है कि कुछ लोग कोविड-19 लॉकडाउन को अवसर के तौर पर ले लिए हैं। इससे इस महामारी के दौरे में पेड़ों का कटाव लगातार जारी है। ऐसे में वहां के राष्ट्रपति बाल्सोनारो के लिए एक चुनौती है कि वह किस तरह इसपर रोक लगाते हैं।

20% ऑक्सीजन यहीं से आता है

बता दें कि अमेजन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट (वर्षावन) है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे 'पृथ्वी का फेफड़ा' भी कहते हैं। यह जंगल 2।1 मिलियन वर्गमील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता, तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। अमेज़न के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाली साफ पानी के लिए। यहां जैव-विविधताओं का भंडार है।

सवाना क्षेत्र में बदल सकता है जंगल

वैज्ञानिक कार्लोस नोबर और थॉमस ई लोवेजाय अपने रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरीके से अमेज़न के जंगलों को काटा जा रहा है, वह दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़े सवाना क्षेत्र में बदल सकता है। बता दें कि सवाना क्षेत्र में छोटे-छोटे पौधों के साथ घास का जंगल होता है। इससे क्षेत्र की इकोलॉजी भी बदल सकती है।

नेशनल जियोग्राफ़िक की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेज़न रेनफॉरेस्ट का असर सिर्फ क्षेत्रीय वॉटर साइकल पर नहीं होता, बल्कि इसका असर ग्लोबल स्केल पर होता है। अमेज़न के जंगलों से जिस तरह बारिश होती है, वह क्षेत्रों से होते हुए पहाड़ों के कोने तक पहुंचती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेज़न रेनफॉरेस्ट के पास वह क्षमता है कि वह जितना बारिश पाता है, उसका आधा प्रोड्यूस कर देता है। यह चक्र एक नाजुक संतुलन है,जिसके टूटने पर गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहीं ब्राजील का रूख भी बहुत निराशाजनक है।

नाई की दुकान से कोरोना संक्रमण का बड़ा खतरा

एजेंसियां : कोरोना संक्रमण के भय से भले आप कितना भी सतर्क रहते हों, पर जरा सी लापरवाही सारी सतर्क ता पर पानी फेर सकती है। और यह लापरवाही है नाई के पास जाना। नाई एक तौलीये से कम से कम 4 से 5 लोगों की नाक रगड़ता है,जानकारी के अनुसार अमेरिका में 50 प्रतिशत मौतें ऐसे ही हुई है जो सैलून होकर आये थे। सबसे बड़ी बात है कि यह खतरा लम्बे समय तक बरकरार रहेगा। जब तक कोरोना एकदम से खत्म नहीं हो जाता हम सैलून जाकर सेविंग कराने बाल कटवाने की सोच भी नहीं सकते। नाई अनेक लोगों के सम्पर्क में रहेगा।

नाई का तोलिया, नाई का उस्तरा नाई का ब्रश, कुर्सी आदि काफी लोग इस्तेमाल करते है। यानि स्थिति सामान्य होने के बाद भी यह खतरा बरकरार रहेगा। सावधान रहें।

E ZONE CARE

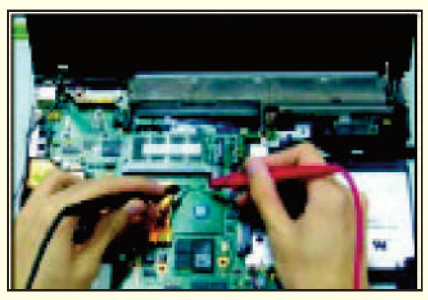

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।